



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 366]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 31, 2005/भाद्र 9, 1927

No. 366]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 31, 2005/BHADRA 9, 1927

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(भारतीय रिज़र्व बैंक)

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 11 अगस्त, 2005

सं. फेमा/139/2005-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (तीसरा संशोधन) विनियमावली, 2005

सा.का.नि. 552(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 (7 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं. फेमा 120/आरबी-2004) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्,

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (तृतीय संशोधन) विनियमावली, 2005 कहलाएंगी।

(ii) ये मई 12, 2005 से लागू समझी जाएंगी। @

2. विनियमावली में संशोधन :—

विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 में :—

- (क) विनियम 6, उप-विनियम 2 के खण्ड (i) में, "शुद्ध मालियत के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा" शब्दों को "शुद्ध मालियत के 200 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ख) विनियम 6 में, उप-विनियम (2) के खण्ड (i) के स्पष्टीकरण में, "शुद्ध मालियत के 100 प्रतिशत की सीमा के अन्दर" शब्दों और अंकों को "शुद्ध मालियत के 200 प्रतिशत की सीमा के अन्दर" शब्दों और अंकों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 1/23/ई एम/2000-IV]

विनय बैजल, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी :—(i) विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 नवम्बर 19, 2004 के सरकारी राजपत्र सं. सा.का.नि. 757(अ) में प्रकाशित हुई थी, तत्पश्चात् इसे अप्रैल 7, 2005 के सरकारी राजपत्र सं. सा.का.नि. 220(अ) और मई 27, 2005 के सं. सा.का.नि. 337(अ) द्वारा संशोधित किया गया है।

(ii) @ यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे निवमावली को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(RESERVE BANK OF INDIA)

(Foreign Exchange Department)

(Central Office)

NOTIFICATION

Mumbai, the 11th August, 2005

No. FEMA 139/2005-RB

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign security) (Third Amendment) Regulations, 2005

G.S.R. 552(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-section (3) of Section 6 and Sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign Security) Regulations, 2004 (Notification No. FEMA.120/RB-2004 dated July 7, 2004) namely :—

1. Short title and commencement :

(i) These Regulations shall be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign Security) (Third Amendment) Regulations, 2005.

(ii) They shall be deemed to have come into force from May 12, 2005. @

2. Amendment of Regulations :

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign Security) Regulations, 2004,

- (a) in Regulation 6, in clause (i) of sub-regulation (2), for the words and figures "shall not exceed 100% of the net worth", the words and figures "shall not exceed 200% of the net worth" shall be substituted.
- (b) in Regulation 6, in Explanation to clause (i) of Sub-regulation (2), for the words and figures "limit of 100% of the net worth", the words and figures "limit of 200% of the net worth" shall be substituted.

[F. No. 1/23/EM/2000-IV]

VINAY BAIJAL, Chief General Manager

Foot Note :—(i) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign Security) Regulations, 2004 were published in the Official Gazette vide No. G.S.R. 757(E) dated November 19, 2004 and subsequently amended vide No. G.S.R. 220(E) dated April, 7, 2005 and No. G.S.R. 337(E) dated May, 27, 2005.

(ii) @ It is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to such regulations.